

जन-जनके हैं योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश म योगा आदित्यनाथ न जा कहा, वा करक दिखाया। मुख्यमंत्री योगा न दूसर कायकाल स पहल लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, एक साल के भीतर उन्हें एक-एक कर पूर्ण कर दिखाया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया-अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 माहों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय-समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। योगी आदित्यनाथ पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों वाले युपी में सभी मंडलों को एयर कनेक्ट करने की महात्वाकांक्षी परियोजना पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। यूपी में 1,225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेस-वे के जाल ने ना सिर्फ यात्राओं को सुगम और तेज बनाया है, बल्कि इनके दोनों ओर डेवलप किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास को भी गति दे रहे हैं।



દેવા સ્તોત્ર

સાધુપત્ર પ્રદાન કરી શકતાં અને આપણું જો પ્રદાન કરી શકતાં

3

जन जन के नेता, गोरक्षपाठाधीशवर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। ये अवसर इसलिए खास है, क्योंकि देश और दुनिया में आज जिस उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा हो रही है, उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने दूसरे कार्यकाल से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे, एक साल के भीतर उन्हें एक-एक कर पूर्ण कर दिखाया। प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया-अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प हो, हर मुद्रे पर योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति समर्पण के भाव से प्रभावशाली काम किया है। इन 6 माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, बल्कि समय-समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाईलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका।

योगी आदित्यनाथ पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले यूपी में सभी मंडलों को एक कनेक्ट करने की महात्वाकांक्षी परियोजना पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। यूपी में 1,225 किलोमीटर तक फैले एक्सप्रेस-वे के जाल ने ना सिर्फ है, बल्कि इनके दोनों ओर डेवलप किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास को भी गति दे रहे हैं। आने वाले समय में यूपी में 6 नये एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जाना है। एक्सप्रेस-वे की रफ्तार के साथ ही प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का जाल बिछाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाये जा रहे हैं, 65 जिलों में मोड़कल कॉलेज के अलावा गोरखपुर-रायबरेली में एस्म का संचालन किया जा रहा है। 6.51 करोड़ प्रदेशवासियों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक के बीमा से कवर किया जा चुका है। मेट्रो को अब गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, बेरेली और मेरठ में भी चलाने की योजना बनाई जा रही है। आगरा में जल्द मेट्रो की सवारी शुरू होने वाली है। मुख्यालय अंसारी सहित 36 माफिया और उनके शागिदों को आजीवन कारावास और दो को फांसी की सजा हुई है। साथ ही पिछले छह माह में प्रदेश स्तर पर चिन्हित 62 माफिया की अवैध रुप से कमाई गई 22 सौ करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त और ध्वन्त किया गया है। सबसे कम समय में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश, देश में पहले स्थान पर है। यूपी युलिस ने माफिया के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ 396 मुकदमे दर्ज कर चार सौ से अधिक

174 पर गुंडा एक, गैंगस्टर में 355 और 13 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है और 310 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ 24 अगस्त से आठ सितंबर तक चले अभियान में पुलिस ने 2833 संदिग्ध आरोपियों का चिह्नित कर 2479 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और 2277 मुकदमे दर्ज किए। वहीं कभी निवेश की राह देखने वाला उत्तर प्रदेश अब इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा राज्य बन गया है। ग्लोबल इंवेस्टर समिट-23 में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अबतक करीब 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए प्रस्तावों से गुजरात सहित दूसरे प्रदेश के समिट में आए निवेश प्रस्तावों का रिकॉर्ड टूटा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा निवेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 94,632 करोड़ रुपए का हुआ है। योगी सरकार में पिछले साढ़े पाँच साल में चार लाख 68 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिसमें तीन लाख 82 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उत्तर चकी हैं।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही सेवायोजन के तहत रोजगार मेला के जरिए 93 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला, जबकि करियर काउसिलिंग के तहत 1,422 लाख से अधिक को मार्गदर्शन मिला।

बाहुबली मापदण्ड योगी राज में आने वाले समय का गठन किया गया है। योगी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में गंगे का चिकित्सा भगतान थर-थर कांप रहा है। सपा-बस्पा की सरकार में बिना

नेतृत्व में आज यूपी चंहु-मुखी विकास की गाथा लिख रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो रहा है। टूटी फटी सड़कें एक्सप्रेस का रूप ले रही हैं, गरीबों के खाते में सीधे सहायता राशि पहुंच रही है। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में रामराज्य की कल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रशांताचार, गुण्डाराज, घोटाला, अपराध, जंगलराज, धांधली, तुष्टीकरण, कोरोना, जबरन धर्मांतरण जैसे राक्षसों पर जबरदस्त प्रहर हो रहे हैं। गुण्डे-माफणियाँ और शिकंजा कसता जा रहा है। बदमाश गले में तख्ती डालकर थाने में स्वयं के पिता का निधन हो गया था। आसबने देखा कि अपने पिता के अंतिम दसां करने की बजाय, उनके अंतिम संस्कर में शामिल होने की बजाय उन्होंने प्रदेश की जनता की सेवा का प्राथमिकता दी। भगवान राम अपने सुख, चैन त्यागकर, मानव कल्प्याना के लिए, राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए पड़े थे। 14 बस्त भग की हवस्तु का त्यागकर प्रभु राम जमीन पर सोए और नगे पैर काटों भरे रासते पर चले। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर दिन रात प्रदेश के जनता की सेवा कर रहे हैं।

लॉजिस्टिक लागत घटने का सुकूनदेह परिवर्त्य

है। इसके साथ-साथ यातायात प्रबंधन में सुधार करके जहां लाजास्टिक लागत का और कम किया जा सकता है, वहीं समय व ऊर्जा की बचत करते हुए दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकती है। ऐसे में आम आदमी से लेकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में पिछले एक-दो वर्षों में लॉजिस्टिक लागत में कुछ कमी दिखाई देने लगी है। हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है



ડા. જયતાલાલ મદારા

લાભકર્તા પાઠ્ય પત્રિકા

ੴ

से समय लाजिस्टिक लागत से सबाधूत विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी करके उत्पादकता और नियंता तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ यातायात प्रवंधन में सुधार करके जहां लॉजिस्टिक लागत को और कम किया जा सकता है, वहीं समय व ऊर्जा की बचत करते हुए दूर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकती है। ऐसे में आप आदिमी से लेकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सकता है। गैरतरतव है कि देश में पिछले एक-दो वर्षों में लॉजिस्टिक लागत में कुछ कमी दिखाइ देने लगी है। हाल ही में प्रक्रियात विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क 2023 में भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अक्टूबर 2021 में घोषित पीएम गति शक्ति योजना और सितंबर 2022 में घोषित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के कार्यान्वयन और वर्ष 2020 से लागू उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के प्रारंभिक अपेक्षित परिणामों से लॉजिस्टिक लागत में कमी आने का परिणय निर्मित होने लगा है। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक के ताजा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तहत कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों, बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट और लॉजिस्टिक क्षमता संबंधी भारत की बढ़त दुनियाभर में रेखांकित हो रही है। आधुनिकीकरण व डिजिटलीकरण से भी भारत का लॉजिस्टिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। सामान्यतया वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजुरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लॉजिस्टिक लागत का क्रम आता है। लॉजिस्टिक लागत का मतलब है उत्पादों एवं वस्तुओं का उत्पादन स्थान से गत स्थान तक पहुंचने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण व अन्य खाली लॉजिस्टिक लागत कम या अधिक हैं में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। यदि सड़कें बेहतर और अबुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपयुक्त तो तेजी से सामान पहुंचने, परिवहन संबंधी चुनौतियां और ईंधन की लागत कम होने से भी लॉजिस्टिक लागत बहुत जाती है। यदि आधारित समय बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाएं पहुंची हैं तो भी लॉजिस्टिक लागत में कमी आती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गति शक्ति योजना करीब 10 लाख करोड़ रुपये व महत्वाकांक्षी परियोजना है लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तु देश में सड़क, रेल, जलमार्ग आदि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह अलग 16 मंत्रालयों और विभागों अधीन है, उनके बीच में सहकार

A large white cargo ship with a multi-level superstructure and several shipping containers, docked at a port. The ship has two tall blue masts and is surrounded by other ships and industrial structures in the background.

पर जार दिकर माल दुलाई क्षमता में सुधार की ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं। इस समय केंद्र सरकार सड़क और रेल मार्ग, दोनों में सुधार पर ध्यान दे रही है। देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक एवं कारोबारी केंद्रों के बीच की दूरी कम करने के लिए एक तरफ डॉडकेट्ड फ्रेट कोरिडोर के जरिए रेल मार्ग से माल दुलाई को तेज करने की कावायद कर रही है, दूसरी तरफ देश के लगभग हर हिस्से में ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही राजमार्गों पर आधारित इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। यह बात भी उभरकर दिखाई दे रही है कि देश में बुनियादी ढांचे के तहत सड़कों, रेलवे, बिजली और हवाई अड्डों के अलावा बंदरगाह से संबंधित सड़क और रेल केन्द्रिकविटी में भी निजी निवेश का प्रवाह अहम भूमिका निभा रहा है। यात्रा के आधार पर भारत का लगभग 95 फीसदी विदेश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देश में नवीनतम बदरगाह नाम के तहत बदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल की शुरूआत देस साथ सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाह की परिचालन जिम्मेदारियां निजी क्षेत्रों को सौंपने की रणनीति देस कारण बंदरगाह विकास और संचालन में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र व भागीदारी तेजी से बढ़ी है। यहां यां भी उल्लेखनीय है कि देश के कोने कोने के शहरी भागों में सड़कों पर बाहरों की भरभरा और इससे यातायात में होने वाली असुविधाओं से जहां समय और ऊर्जा की हानि होती है वहाँ इसका उत्पादकता एवं सकारात्मक घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विश्व स्तरीय सड़कों के मापदंडों पर सड़क नियमित पर काफी धनराश खर्च की जाती है मगर यातायात सुगम बनाने के परिप्रेक्षण में उत्पुत्तु पार्किंग पर पर्याप्त खर्च चाहिए जो नहीं दिया जाता है। ऐसे में चाह चालक सड़कों के किसी भी हिस्से पर वाहन खड़ा करना शुरू कर देते हैं

तकनीक के टिंबोरे बीच भीषण देल हादसे कब तक?

ऋतुपर्ण दत्त

सेंसेक्स
61431.32 पर बंद
निपटी
18130.76 पर बंद

देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें

@Pratahkiran

www.pratahkiran.com



पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में मौका, चीन और जापान बेहतर उदाहरण

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के जितने भी देश आज पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के आंकड़े को पार कर रहे हैं, उन सभी को शेयर बाजार तक बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है दो लाख करोड़ डॉलर से पांच लाख करोड़ डॉलर की ताजा पूरी किए। आंकड़े बताते हैं कि तीन प्रमुख देशों अमेरिका, चीन और जापान इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं।

चीन की अर्थव्यवस्था 2004 से 2009 के बीच दो लाख करोड़ डॉलर से पांच लाख करोड़ डॉलर हुई। इस दौरान इसका शेयर बाजार हॉल्सेंग 8,500 से 32,000 तक पहुंच गया। यानी इसने 5 साल में करीब 4 गुना की वृद्धि हासिल की।

जापान की अर्थव्यवस्था 1978 में दो लाख करोड़ डॉलर की थी और 8.5 साल बाद 1986 में यह पांच लाख करोड़ डॉलर की बनी। 1978 से 1991 के दौरान इसका शेयर बाजार ने 14 गुना की वृद्धि हासिल की। यह 2000 से बढ़कर 27,000 पर पहुंच गया।

अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1977 में दो लाख करोड़ डॉलर की थी। 1988 में 5 लाख करोड़ डॉलर हुई। शेयर बाजार डाउनजॉइस 1977 से 2000 के बीच 17 गुना बढ़ा, जो 700 से बढ़कर 12,000 के पार पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार का रुद्धान भी ऐसा ही है। अक्टूबर, 2021 में सेंसेक्स ने पहली बार 62,000 और पिछे 63 हजार को पार किया।



भारत की अर्थव्यवस्था इस समय करीब 3.5 लाख करोड़ डॉलर की है जो 2026-27 तक 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी।

दुनिया के कई देशों के अमर पांच लाख गुना की वृद्धि हासिल की है। मार्च, 2020 में करीब 3 समय से सेंसेक्स 26 हजार से नीचे चला गया था जो अब 63 हजार के पार है।

विविधीकरण का मिलता है

फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार

के इस माहील में इकट्ठी सेविंग्स फंड में निवेश

बेहतर हो सकता है। इसमें कम से कम तीन एसेट बलास होते हैं जिनके जियो अपको विविधीकरण का फायदा मिलता है। ऐसा इमरित, जोकि इस सेविंग्स में निवेश को जो हिस्सा है, वह बहलता रहता है। यही कारण है कि इस फंड में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलता है। आईसीआईसीआई एस्ट्रोव्यूशनल इकिटी सेविंग्स फंड इस सेंसेक्स में एक बेहतर फंड बनाया है। यह विविधीकरण का एक तरीका है।

वैश्विक आर्थिक मंदी और कई अन्य कारणों से इकट्ठी बाजार अस्थिर है। मैट्स्ट्रॉक भी बहुत सत्ता नहीं है। ऐसे में इकट्ठी सेविंग्स फंड निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। - दिव्या अम्बाल, फिनेक्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेस

डेट और इक्षिटी वाले सेविंग्स बुनें

आम तौर पर, इक्षिटी आवंटन के लिए फंड ऐनेजर लार्ज कैप पसंद करते हैं। जब डेट की बात आती है, तो आवंटन एएर रेटेड एपर या कम अवधि वाली सेवाकारी को बहुती की वृद्धि रहती है। जहाँ तक कंजदाताओं की बात है तो वित वाले 2018-19 के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वसूली है। उस समय 77 दिवाला समाधान प्रक्रियाओं से वसूली 1.11 लाख करोड़ की रही थी। इससे एक निवेश सीमा तक इकट्ठी जाखिम की रोंगटे होती है और अस्थिरता को

नियन्त्रित करने में भी मदद मिलती है।

हीरा मोटोकॉर्प ने 6,000 रुपये तक बढ़ाए इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम

हीरा मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक स्कूटर वीआईडी वी 1 प्रो की कीमत 6,000 रुपये तक बढ़ा कर 1,45,900 रुपये कर दी है। कंपनी ने कहा, फेम-2 की सर्विसड़ी को घटाने के कारण उसे ऐसा करना पड़ा है। फेम-2 के तहत पहले सर्विसड़ी एक्सप्रैक्टर के भाव पर 40 प्रतिशत मिलती थी जो अब 15 प्रतिशत हो गई है।

सीएलटी : 51,424 करोड़ वसूली

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने वित वर्ष 2022-23 में फंड ऐनेजर लार्ज कैप पसंद करते हैं। जब डेट की बात आती है, तो आवंटन एएर रेटेड एपर या कम अवधि वाली सेवाकारी को बहुती की वृद्धि रहती है। जहाँ तक कंजदाताओं की बात है तो वित वाले 2018-19 के बाद यह दूसरी सर्वाधिक वसूली है। उस समय 77 दिवाला समाधान प्रक्रियाओं से वसूली 1.11 लाख करोड़ की रही थी। इनमें एसार स्टील और मोनेट इस्पात जैसे मामले भी शामिल थे।

500 करोड़ से कम की मार्केट कैप वाली कंपनियों पर लागू हुआ ईएसएम फ्रेमवर्क



नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार में छोटे शेयरों में उत्तर-चाहूवाल को रोकने के लिए बांधी स्टॉक एस्ट्रेचेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोमवार (5 जून, 2023) से ईएसएम को लागू किया। दोनों एक्सचेंज की ओर से नियंत्रित निवेशकों के द्वारा गया था।

एसएम और बीएसएम की ओर से शुक्रवार को जारी हुए दो अलग-अलग सर्कुलर में बाजार नियामन सेवी और एक्सचेंज के बीच द्वारा एक ज्ञाइंट बैठक में तब किया गया है कि 500 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाली माझी स्मॉल कंपनियों पर ईएसएम फ्रेमवर्क लागू किया जाए।

एसएच की ओर से बताया गया ईएसएम फ्रेमवर्क के तहत शेयर में ट्रैडिंग ट्रैडर्स और मैकेनिज्म के तहत 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के प्राइस बैंड में होती है। इसमें दो स्टेज होती है। कोई भी शेयर इस फ्रेमवर्क के मार्केट में बदलने के लिए रहता है। वर्ती, अगर वह ईएसएम फ्रेमवर्क की स्टेज 2 में चला जाता है तो उसे कम से कम एक फ्रैम महीने के लिए रहना होगा। एक्सचेंज की ओर से बताया गया था कि एक फ्रैम वर्क की स्टेज 2 में एक महीना पूरा करने के बाद बाद शेयर में 8 प्रतिशत के कम का उत्तर-चाहूवाल आता है जो कि उसे स्टेज 1 में भेजा जाएगा।

अप्रतिरोधी पर देखा जाता है कि 500 करोड़ से कम की मार्केट कैप वाली कंपनियों में जल्द उत्तर-चाहूवाल आता है। कई बार ये शेयर सर्किट दूसरी सर्किट चलते हैं और इसमें गड़बड़ी भी सबसे अधिक होती है। ऐसे में ईएसएम फ्रेमवर्क लागू से निवेशकों को लाभ होगा।

सिस्टम अपग्रेड के कारण दो दिन नहीं मिलेंगी एचडीएफसी बैंक की सेवाएं



ग्राहकों के लिए रहती बात है कि वे सिस्टम के रखरखाव और अपग्रेड का कार्य सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किया जाए। इस समय बैंकोंग सेवाओं का आमतौर पर कम इस्तेमाल होता है।

कौन-सी सेवाएं रहेंगी बंद?

बैंक की ओर से किए गए मेल के मुताबिक, बैंलेंस चेक करने, डिपाजिट, फंड ट्रांसफर, और अन्य भागातां से जुड़ी सेवाएं 10 जून और 18 जून को बंद रहेंगी।

बैंक द्वारा सिस्टम अपग्रेड करने के लिए 4 जून को सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच बैंकोंग सेवाओं को बंद रहा गया था। इसके साथ ही बैंक द्वारा मेल में कहा गया कि डाउनटाइम को कम करने की हर संभव कोशिश किया जाएगा।

एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए मेल में लिखा गया कि हम अपने ग्राहकों के लिए प्रतिक्रिया देंगे हैं और हार्डिंग होकि वहाँ ने वित वर्ष 23 की चौथी तिमाही और अप्रैल वर्ष 23 की चौथी तिमाही को बंद रहा गया था। इसे कारण के लिए एक ड्रेटेड एपर था। अप्रैल से एक्सप्रैक्टर के लिए थोड़े समय के लिए अपने कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। ये कदम बैंक ने अपने अपग्रेड करने के लिए उठाया है।

एचडीएफसी बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए मेल में लिखा गया कि हम अपने ग्राहकों के लिए प्रतिक्रिया देंगे हैं और हार्डिंग होकि वहाँ ने वित वर्ष 23 की चौथी तिमाही और अप्रैल वर्ष 23 की चौथी तिमाही को बंद रहा गया था। इसे कारण के लिए एक ड्रेटेड एपर था। अप्रैल से एक्सप्रैक्टर के लिए थोड़े समय के लिए अपने कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। ये कदम बैंक ने अपने अपग्रेड करने के लिए उठाया है।

सर्विस सेवाएं दो दिन बंद होंगी जबरदस्त तेजी, पीएमआई 61.2 अंक रहा



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के सर्विस सेवाकर की ग्रोथरेट में मई में बढ़ा देखने को मिलती है और ये बिल्ले 13 सालों के उत्तमतम स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। सर्विस सेवाकर में तेजी की वजह मांग बढ़ा और कंपनियों के नए ग्राहकों में वृद्धि होना है। सोमवार को जारी हुए एक मासिक सर्विस में ये बातें कही गईं।

एसएचडी ग्लोबल ईडिया सर्विसेज का पीएमआई डाटा सोमवार को जारी किया गया था। यह

